10 पायदान की ऊंची छलांग

कारोबारी सहूलियतों में यूपी 12वें से दूसरे स्थान पर

योगी सरकार के निवेश का माहौल बनाने के प्रयासों पर मुहर ■ निवेश की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार में प्रदेश में कारोबारी सहूलियतों (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के वजन पर मुहर लग गई है। व्यापार और उद्योग का माहौल तैयार करने में यूपी ने 10 पायदान की ऊंची छलांग लगाते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इससे यूपी वैश्विक स्तर पर निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर सकेगा और निवेश गतिविधियों में और तेजी आएगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2019 की रैंकिंग जारी की। आंध्र प्रदेश कारोबारी सहूलियतों में अव्वल रहा।

मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल व अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से प्रदेश की इस उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों के काम के आधार पर प्रदेश 12वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार जब अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करने में लगी है, कारोबारी सुगमता की टॉप रैंकिंग से सरकार के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है।

(वर्ष 2019 में भारत भी कारोबारी सुगमता की वैश्विक सूची में 63 स्थान ऊपर पहुंचकर 63वें पायदान पर रहा। जबकि 2014 में 142वें स्थान पर था।)

महाना बोले- यूपी में नए युग की शुरुआत

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद औद्योगीकरण के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। यूपी के इतिहास में यह बड़ी उपलब्धि है। लोगों का विश्वास बढ़ा है कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और जीडीपी को ध्यान में रखकर काम हो रहा है। लक्ष्य यूपी को नंबर-1 पर लाने का है। - सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री

186 सुधारों पर काम कर सुधारी रैंकिंग

केंद्र ने बीआरएपी-2019 में 187 सुधारों पर काम का प्रस्ताव दिया था। इनमें एक सुधार प्रदेश पर लागू नहीं हो रहा था। राज्य ने 186 सुधारों को क्रियान्वित किया। मूल्यांकन में 184 सुधार केंद्र की कसौटी पर खरे पाए गए।

निवेश मित्र, श्रम सुधारों से बदला माहौल

- योगी सरकार ने पचास सेवाओं को ऑनलाइन कर निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा।
- बड़े पैमाने पर श्रम सुधारों को लागू करने की पहल कारगर साबित हुई।

इन्वेस्टर्स समिट से तेज हुई कारोबारी सुधारों की मुहिम

अब तक 1.65 लाख करोड़ के निवेश

निवेश व रोजगार सृजन का माहौल बनाने के लिए योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी प्रमुख सेक्टर की नीतियां बनाईं और कारोबारी सुधार लागू किए। नतीजा यह हुआ कि फरवरी-2018 में इन्वेस्टर्स समिट में 4.28 लाख करोड़ के एमओयू हुए। इनमें से 1.65 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। इनमें से तमाम ने व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इसी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल विंडो निवेश मित्र सिस्टम का शुभारंभ कराया गया था। इस पोर्टल से निवेशकों को घर बैठे अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस, क्लीयरेंस व शुल्क जमा करने जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिल गईं। इस सुविधा को 72.9 फीसदी ने इसे सराहा।

बढ़ती उम्मीदें

3300 करोड़ के नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी जल्द, 5000 को मिलेगा रोजगार

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों के साथ करीब 3343.51 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर वित्तीय सुविधाएं व रियायतें देने की संस्तुति कर दी है। इसे मंजूरी के लिए अब कैबिनेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है। इन प्रोजेक्ट के स्थापित होने से प्रदेश में करीब 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। समिति ने जिन प्रस्तावों पर निवेश की संस्तुति दी है, इनमें सभी 100 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। - पेज 3